>

Title: Need for effective implementation of centrally sponsored food, health & employment schemes in the Country.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदय, ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्ष 2009 के अनुसार देश के लगभग 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से पीड़ित है। इसका प्रमुख कारण यह है कि देश के अधिकतर ग्रामों या आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को बुनियादी भोजन भी उपलब्ध नहीं करा पाते, इसलिए बच्चे बीमार हो जाते हैं तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवा न होने के कारण बच्चों का ढंग से टीकाकरण नहीं हो पाता है और न ही उनकी बीमारियों का समुचित ईलाज।

वास्तव में यह एक विडंबना है कि देश में एक ओर जहाँ गोदामों में अनाज भरा पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ भूख से मौतों का सिलसिला भी जारी है। आम तौर पर केन्द्रीय योजनाओं का वास्तविक लाभ गरीबीं को नहीं मिल पाता। सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए बनी है। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनाज जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच रहा है। इसी तरह से नरेगा में भी अनियमितता की अनेक खबरें प्रकाश में आती रहती है।

मेरा सरकार से अनुरोध हे कि वह केन्द्रीय योजनाओं का जरूरतमंदों तक लाभ सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये।